



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 अयोध्या मुद्दे पर आस्था से किया जा रहा है समझौता : अखिलेश

6 साइबर संजाल: डिजिटल दुनिया का काला सच

7 उत्साह के साथ मनाया दलाई लामा का 91वां जन्मदिन

फास्ट टैक

श्रीलंका जेल हिंसा : मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हुई

कोलंबो/भाषा। श्रीलंका के पश्चिमी तटीय शहर नेगोम्बो की एक जेल में हुई हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। क्षमता से अधिक कैदियों वाली इस जेल में रविवार को कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जब उपद्रवी कैदियों ने जेल के हथियारों पर कब्जा कर लिया तो फिर से हिंसा भड़क गई। 'हीरु न्यूज' ने प्राधिकारियों के हवाले से बताया कि झड़पों और उसके बाद जेल में हुई हिंसा में 25 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 अन्य घायल हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 को उपचुनाव

नई दिल्ली/भाषा। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये सीटें तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीनों सीटें जीतने की संभावना है। तृणमूल के जिन तीन राज्यसभा सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, उनमें सुखेंद्रु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चक्र बड़ाइक शामिल हैं। इन तीनों ने जून में अलग-अलग लिथियों पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए अपने पद छोड़े थे।

इसरो को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी का ईमेल

बेंगलूरु/भाषा। बेंगलूरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय को सोमवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने यह जानकारी दी। तलाशी के दौरान हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे यह संदेश फर्जी साबित हुआ। कुछ दिन पहले भी मुख्यालय को इस तरह की धमकी मिली थी जो बाद में अफवाह साबित हुई। पुलिस ने बताया कि धमकी की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी, ध्वन दस्ता और बम निरोधक दस्ता न्यू बीईएल रोड स्थित इसरो के परिसर में पहुंचे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया और इमारत की गहन तलाशी ली गई। पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल से धमकी भेजी गई थी संजय नगर थाना पुलिस उसके स्रोत की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इसका दो जुलाई को भेजे गए फर्जी ईमेल से कोई संबंध है।

07-07-2026
सूर्योदय 6:39 बजे

08-07-2026
सूर्यास्त 5:50 बजे

BSE
78,285.07
(+ 521.16)

NSE
24,430.35
(+159.50)

सोना
15,108 रु.
(24 कैरर) प्रति ग्राम

चांदी
243,000 रु.
प्रति किलो

मिशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सूते हाल

हर गाँव शहर में बने हुए, अनगिन अवैध निर्माण कई। जिनकी है खबर सभी को ही, शासन के पास प्रमाण कई। जब भी होती दुर्घटनाएं, निर्दोष गँवाते प्राण कई। दोषी को मिलती नहीं सजा, पा जाते न्यायिक त्राण कई।।

‘अनुच्छेद 370 को हटाने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है। उन्होंने मुखर्जी को एक दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था। मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश एक ऐसे नेता के योगदान को याद कर रहा है, जिनके आदर्श पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमारा देश महान दूरदर्शी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहा है। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 को हटाकर हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विचार के पक्षधर थे और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। भारत के बंटवारे के समय मुखर्जी की भूमिका का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पूरे बंगाल को



पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनसंघ के संस्थापक ने इसके खिलाफ जन्मत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने उस दौर की मुखर्जी की एक बात याद दिलाई कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, मैंने पाकिस्तान का बंटवारा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी एक मजबूत वैकल्पिक आवाज के तौर पर तब उभरे, जब कांग्रेस के दौर में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। मोदी ने उन कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने मुखर्जी द्वारा रखी गई वैचारिक नींव को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में मदद की। उन्होंने कहा, कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ की विचारधारा और सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। जनसंघ से भारतीय

मुखर्जी एक मजबूत वैकल्पिक आवाज के तौर पर तब उभरे, जब कांग्रेस के दौर में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। मोदी ने उन कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने मुखर्जी द्वारा रखी गई वैचारिक नींव को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में मदद की। उन्होंने कहा, कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ की विचारधारा और सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। जनसंघ से भारतीय

जनता पार्टी बनने के सफर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी अपने संस्थापक के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा, जो कभी भारतीय जनसंघ था, वह आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बनकर लोगों की सेवा कर रहा है। मुखर्जी की स्थायी विरासत पर भरोसा जलाते हुए मोदी ने कहा कि भविष्य की पीढ़ियाँ, जो भाजपा के इतिहास का अध्ययन करेंगी, उनके योगदान को हमेशा मानती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि जब आने वाली पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखेंगी, तो वे निश्चित रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों, साहस और उनकी दूरदर्शी सोच का जिक्र करेंगी।

व्हाट्सएप को यूजरनेम विवाद पर जवाब के लिए सरकार से मिला अतिरिक्त समय

नई दिल्ली/भाषा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप संदेश मंच व्हाट्सएप को विवादित 'यूजरनेम' फीचर पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, व्हाट्सएप ने आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ चर्चा पूरी नहीं होने तक इस फीचर को भारत में लागू नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सएप को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के नोटिस पर जवाब देने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले जवाब देने की अंतिम तिथि शुक्रवार की निर्धारित थी। यूजरनेम फीचर के तहत उपयोगकर्ता फोन नंबर साझा नहीं करने के बावजूद मैसेजिंग मंच

पर संवाद या चैट कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह इस प्रस्तावित फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था और आशंका जताई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले और प्रतिरूपण के मामलों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इस फीचर को परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक रोकने को भी कहा था। सूत्रों के अनुसार, मेटा की एक टीम ने पिछले शुक्रवार को आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। नोटिस में सरकार ने मेटा से यह स्पष्ट करने को कहा था कि ऐसे फीचर के चलते साइबर अपराध बढ़ने की आशंका को देखते हुए आईटी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।



भारी बारिश से मुंबई बेहाल, पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात ठप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/पुणे/भाषा। मुंबई और उमरके आसपास के शहरों में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश ने इन इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया और कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण अधिकारियों को महत्वपूर्ण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा और कुछ खंडों पर रेलवे परिचालन को निलंबित करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि पुणे जिले की मावल तहसील के पाटन गांव में भूस्खलन के कारण एक घर के मलबे में दब जाने से दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुणे की खेड़ तहसील में बाढ़ की चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि पिछले तीन से चार दिनों



भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को और मजबूती देने मोदी इंडोनेशिया पहुंचे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जकार्ता/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'महासागर विजन' तथा एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। विशेष सड़कवर्षा के तहत हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो ने किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की अगुवानी करने के लिए चार मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया और उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, जकार्ता पहुंच गया हूँ। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो द्वारा मेरा स्वागत किए जाने की सद्भावना से मैं बहुत प्रभावित हूँ।

वर्ष 2018 में संबंधों को व्यापक 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाए जाने के बाद से इंडोनेशिया की यह मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी ने कहा, "2018 में इंडोनेशिया की मेरी पहली यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जिससे हमारे लोगों को लाभ हुआ है।" उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में इस साझेदारी को और 'गति देना' है। मोदी ने कहा, राष्ट्रपति प्रबोयो और मैं योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। इससे हमारे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। इंडोनेशिया में रहने के दौरान, मैं भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। योग्याकार्ता शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित यह सदियों पुराना मंदिर इंडोनेशिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है। दिल्ली से रवाना होने से

पहले, मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'महासागर विजन' और साथ ही मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत के प्रति हमारे नजरिए' को और मजबूत करेगी। महासागर, यानी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए पारस्परिक एवं समग्र विकास', सभी क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए भारत का विजन है।

मोदी की यह यात्रा जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति प्रबोयो की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है। उन्होंने कहा, "भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत एवं लोगों के आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं, तथा मेरी यह यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और मजबूत करेगी।" इंडोनेशिया से मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे। यात्रा के आखिरी चरण में वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के न्योते पर ऑकलैंड पहुंचेंगे।

‘भारत टैक्सी’ की तर्ज पर नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनेगी : अमित शाह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा की कि सहकारी संस्थाओं के कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि 'भारत टैक्सी' की सेवाओं का विस्तार अगले दो साल में 500 शहरों तक किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारत के सहकारी तंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पेशेवरों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार समाप्त करने पर जोर दिया। शाह ने कहा कि मंत्रालय की स्थापना से भारत के सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है, जिसे कांग्रेस शासन के दौरान 'उपेक्षित आंदोलन' बनाया गया था। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं, जिनके 30



करोड़ से अधिक सदस्य हैं। मंत्री ने मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, जिनमें सहकारी तंत्र में पारदर्शिता और पेशेवर व्यवस्था लाने के प्रयास शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सहकारी मॉडल के तहत शुरू की गई कैब सेवा से जुड़े मंच 'भारत टैक्सी' का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अगले दो वर्षों में इसका विस्तार 500 शहरों

तक किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा, "भारत टैक्सी" की तर्ज पर हम सहकारी क्षेत्र में एक जीवन बीमा कंपनी स्थापित करेंगे। इससे बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के विकास में मदद मिलेगी।" उन्होंने कहा कि उर्वरक क्षेत्र की सहकारी संस्था इफको का संयुक्त उद्यम इफको-टोकियो पहले से ही बीमा कारोबार में है। भारत में वर्तमान में 26 जीवन बीमा कंपनियां हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने

महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच जारी रहने के बीच सोमवार को यहां एक बैठक के दौरान अपने महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर सदस्य कृष्ण

मोहन को महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का भी निर्णय लिया गया। यह बैठक शाम को समाप्त हुई, जिसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कार्यक्रम स्थल से चले गए। बैठक राम जन्मभूमि परिसर के अंदर दोपहर करीब सात तीन बजे शुरू हुई जिसमें ट्रस्ट के नौ स्थायी सदस्यों में से सात ने भाग लिया।

मंदिर के दान के गबन के आरोपों के बाद राय और मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफे पर विचार-विमर्श करने, मामले की एसआईटी जांच की प्रगति की समीक्षा करने और इस्तीफे स्वीकार किए जाने पर ट्रस्ट में प्रमुख पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा करने के



लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले, ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि वह राम लला मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से "बहुत दुखी" हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि कथित अपराध से जुड़े सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। राम मंदिर परिसर के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, संपर्क मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। मीडिया कर्मियों एवं अन्य लोगों के निजी वाहनों की आवाजाही पर

प्रतिबंध लगाया गया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बैठक स्थल को मणिराम दास छावनी से मंदिर परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

मंदिर के दान की कथित चोरी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक एसआईटी ने पिछले महीने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सांपी थी, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने हटाए गए सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ आरोपी मंदिर परिसर से बाहर जाते समय नोटों को छिपाते हुए नजर आ रहे हैं।



बाढ़ के कारण आलंदी का संपर्क कटा, वरकारियों से यात्रा स्थगित करने की अपील

पुणे/भाषा। इंद्रायणी नदी में ऊफान के चलते आलंदी तक जाने वाले मार्ग के चारों पुल जलमग्न हो जाने के मद्देनजर पुणे जिला प्रशासन ने सोमवार को वरकारियों और श्रद्धालुओं से संत ज्ञानेश्वर महाराज की आगामी पालखी यात्रा में शामिल होने के लिए यहां नहीं आने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को पुणे के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है और जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आठ जुलाई को निकलने वाले पालखी जुलूस के लिए हजारों श्रद्धालुओं के शहर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकारियों ने शहर को आगम्य घोषित कर दिया है और अपील की है कि जो लोग पहले से ही रास्ते में हैं, वे बाढ़ के मद्देनजर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा तत्काल रोक दें। प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘इंद्रायणी नदी पर बने जिन चारों पुलों के माध्यम से आलंदी तक पहुंचा जा सकता है, वे बाढ़ के कारण डूब गए हैं। फिलहाल इस शहर की यात्रा करना सुरक्षित नहीं है।’ उसने यात्रा के लिए निकल चुके वरकारियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी मौजूदा जगहों पर ही रुक जाएं और अगले आदेश तक शहर में प्रवेश न करें।



सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की

नई दिल्ली/भाषा। नवनिर्भुक्त थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा की। राष्ट्रपति कार्यालय ने पोस्ट में कहा, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपनी पत्नी श्रीमती कोमल सेठ के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनरल धीरज सेठ ने 30 जून को नए थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके पास पश्चिमी मोर्चों पर सेना की दो परिचालन कमानों का नेतृत्व करने का अनुभव है।

इमारात बनी नहीं, फिर भी होती रहीं नियुक्तियां और तबादले, चर्चा में इंदौर का ‘घोस्ट हॉस्पिटल’

इंदौर/भाषा। इंदौर में घनी आबादी वाले खजराना इलाके में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की इमारात सरकारी मंजूरी के छह साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है, लेकिन इस अस्पताल के लिए स्वीकृत 87 पदों पर नियुक्तियां और कर्मचारियों के तबादले होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग महज कागजों पर जारी इस परियोजना को ‘घोस्ट हॉस्पिटल’ जैसे नामों से संबोधित करते हुए प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अस्पताल का भवन ही अस्तित्व में नहीं है, तो उसके नाम पर तबादले भला किस आधार पर किए जा रहे हैं?

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि खजराना और आस-पास के क्षेत्रों में करीब पांच लाख की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 बिस्तरों वाले नये सिविल अस्पताल की कवायद 2019 में शुरू की गई थी और 2020 में इसके निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि यह मंजूरी मिलते ही चिकित्सकों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट आदि के कुल 87 पद तय सरकारी प्रक्रिया के तहत अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘खजराना सिविल अस्पताल के लिए हमें जमीन का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन अब तक हमें जमीन का कब्जा नहीं मिला है जिससे यह जमीन निर्माण एजेंसी के सुपुर्द नहीं की जा सकी है।’’ हासानी ने कहा कि अस्पताल का निर्माण समय पर नहीं हो सका, इसलिए अस्पताल के लिए स्वीकृत स्टाफ का उपयोग शहर के 85 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में किया जा रहा है।

भारी बारिश की वजह से मुंबई आ रही पांच उड़ानों का मार्ग बदला गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से सोमवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे तक मुंबई आ रही पांच उड़ानों के मार्ग में बदलाव कर संबंधित विमानों को दूसरे स्थानों पर उतारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बयान में बताया कि रायपुर से आ रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 595 और सिंगापुर से आ रही उड़ान 6ई 1340 का मार्ग बदलकर इन विमानों को हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतारा गया जबकि दिल्ली से आ रही आकासा एयर की उड़ान क्यूपी 1110 (दिल्ली-मुंबई) को अहमदाबाद भेजा गया। निजी विमानन कंपनियों ने एक बयान में बताया कि कोलकाता से आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआई 2772 और मस्कट से आ रही ओमान एयर की उड़ान डब्ल्यूवाई203 (मस्कट-मुंबई) को क्रमशः बेंगलूर और यडोदरा हवाई अड्डों पर उतारा गया। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।



भारी बारिश से पश्चिम रेलवे का परिचालन टप, लंबी दूरी की 20 से अधिक ट्रेनें फंसीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने से सोमवार को पश्चिम रेलवे का परिचालन पूरी तरह चरमरा गया। इसके कारण लंबी दूरी की 20 से अधिक ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। ट्रेन सेवाओं के निरस्त होने, उनके मार्ग में परिवर्तन तथा विलंब के कारण 40 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके मद्देनजर रेल प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए राहत कार्य तेज करने के साथ ही मुंबई-अहमदाबाद मुख्य रेलमार्ग पर यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, वसाई रोड-विरार और सफाले-पालघर रेलखंडों के बीच भारी जलभराव के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर सबसे बुरा असर पड़ा है। अपराह्न 1.50 बजे तक विरार, वागागांव, पालघर, दहानू रोड और वलसाड जैसे स्टेशनों पर लंबी दूरी की कम



से कम 22 ट्रेनों को रोक कर रखा गया था। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिनभर में कुल 40 से अधिक ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के मद्देनजर कम से कम आठ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, 10 को निरस्त करना पड़ा, जबकि कई ट्रेनों को उनके तय गंतव्य से पहले के स्टेशनों पर ही समाप्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र के पालघर जिले में सुबह महज दो घंटे के भीतर लगभग 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे सुबह नौ बजे तक स्थिति बेहद गंभीर हो गई। इस व्यवधान के कारण बांद्रा टर्मिनस-श्री माता वैष्णो देवी कटारा एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल-

हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस और दादर-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस सहित करीब आठ प्रमुख ट्रेनें रास्ते में ही फंसी रहीं। वहीं, जलमग्न मार्ग पर ट्रेनों का दबाव और न बड़े, इसके लिए अहमदाबाद, जोधपुर और भुज की ओर से आने वाली ट्रेनों को वापी और सूरत स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। इस संकट की स्थिति में पश्चिम रेलवे ने स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) की मदद से यात्रियों के लिए भोजन, पानी और जलपान की व्यवस्था की। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि पालघर में हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों को भोजन के करीब 500 पैकेट बांटे गए। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस और सूरत जैसे बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं। मुख्य रेल मार्ग के साथ-साथ मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली उपनगरीय (लोकल) ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। बोरीवली और चवगेट के बीच लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चलीं, जबकि विरार-दहानू खंड पर परिचालन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा।

अभिनेता मोहनलाल ने पास 10 हाथीदांत और उससे बनी 13 मूर्तियां, वनविभाग को दी सूचना

कोझि। अभिनेता मोहनलाल ने केरल वन विभाग को जानकारी दी है कि उनके पास 10 हाथीदांत और उससे बनी 13 मूर्तियां हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अभिनेता ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है जब यह वन्यजीवों से जुड़ी चीजें गैर-कानूनी तरीके से रखने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मलयत्तर संभागीय वन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह जानकारी विभाग की माफी योजना के तहत दी गई है जिसके माध्यम से लोग अपने पास मौजूद वन्यजीव वस्तुओं की स्वेच्छा से घोषणा कर सकते हैं। अभिनेता ने इससे पूर्व चार हाथीदांत होने की जानकारी दी थी और अब उन्होंने छह और हाथी दांत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाथीदांत से बनी जिन मूर्तियों की जानकारी दी गई है, उनमें भगवान कृष्ण, भगवान राम और तिरुपति बालाजी की मूर्तियां शामिल हैं और इनका कुल वजन लगभग 46 किलोग्राम है। मोहनलाल ने दावा किया कि उनके पास मौजूद अधिकतर हाथीदांत उन्हें विरासत में या तोहफे के तौर पर मिले थे। अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग इन हाथी दांतों और उनसे निर्मित मूर्तियों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पर मिले थे। अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग की माफी योजना के तहत लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बिना पंजीकरण वाली वन्यजीवों से जुड़ी चीजों की जानकारी दे सकते हैं। मोहनलाल वर्तमान में वन्यजीव के एक मामले में अवैध रूप से चार हाथीदांत रखने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।



वैष्णव ने नांदेड़-मुंबई और टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नांदेड़-मुंबई और टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखायी। इसके साथ ही उन्होंने टनकपुर-पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक किए जाने का भी उद्घाटन किया। वैष्णव ओडिशा के दौर पर हैं, जहां वह भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ-साथ दिन में बाद में ओडिशा से शुरू होने वाली दो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने नई रेल सेवाओं की शुरुआत यहां रेल सदन से की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि नई रेल सेवाओं से रेल संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और

उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले सिख समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘तराई क्षेत्र में रहने वाले हमारे सिख भाई-बहनों की ओर से लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग की जा रही थी। आज नांदेड़ से वाशिम और हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए भी रेल सेवा शुरू की गई है, जिससे विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों का मुंबई से संपर्क बेहतर होगा। पीलीभीत, आगरा और टनकपुर को जोड़ने वाली कुछ अन्य रेल सेवाएं भी शुरू की गई हैं।’’ वैष्णव ने कहा कि रेलवे खटीमा और बनबसा स्टेशनों पर इस ट्रेन के उद्घाटन की मांग पर भी विचार करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यदि यह संभव हुआ, तो इस ट्रेन का उद्घाटन खटीमा और बनबसा में भी निश्चित रूप से किया जाएगा।’’ रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि टनकपुर-पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले विशेष ट्रेन के रूप में संचालित होने वाली टनकपुर-आगरा रेल सेवा को अब नियमित कर दिया गया है।

भारी बारिश के बीच उत्तरी मुंबई में मनोरी तट के पास जहाज फंसा : पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। उत्तरी मुंबई में मनोरी तट से करीब एक किलोमीटर दूर भारी बारिश के बीच सोमवार को एक जहाज फंसा गया। चूंकि यह क्षेत्र चट्टानी है और तेज हवाओं के कारण राहत कार्यों के लिए छोटे जहाजों का वहां जाना असुरक्षित है, इसलिए स्थानीय पुलिस ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को

इसकी सूचना दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोराई थाने के एक अधिकारी ने बताया कि फंसे हुए जहाज के बारे में सुबह जानकारी मिली और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार नौसेना, तटरक्षक बल (आईसीजी) तथा अन्य संबंधित समुद्री प्राधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा, जहाज मनोरी तट से करीब एक किलोमीटर दूर फंसा हुआ है। जहाज ने लंगर डाल दिया है और इससे जुड़ी

किसी अभिय घटना की सूचना नहीं है। अधिकारी ने बताया कि समुद्री एजेंसियों के अधिकारी स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं। स्थानीय मछुआरों ने कहा कि यह क्षेत्र चट्टानी है और तेज हवाओं के कारण छोटे जहाजों के लिए उस फंसे जहाज की ओर जाना असुरक्षित हो गया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।



पॉइंट्समैन की मौत के बाद रेल कर्मचारियों का विरोध, 12 घंटे का इ्यूटी रोस्टर हटाने की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। ‘ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन’ (एआईपीएसए) ने एक जुलाई को नागपुर के गुडमा स्टेशन पर ट्रेन संचालन में मदद करते समय सदस्य की मौत के बाद 12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को खत्म करने की मांग की है। अधिकारियों ने बताया, एक जुलाई को गुडमा स्टेशन पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन अभिलाष यादव को टाटा नगर एक्स. ने टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, इस स्टेशन पर एक ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद उन्होंने (यादव ने) उसे बगल वाली पटरी पर ले जाकर स्थिर करवाया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसी पटरी पर टाटा नगर एक्सप्रेस आ रही थी। भारतीय रेलवे

में पॉइंट्समैन को कांटेवाला भी कहा जाता है, जिनकी जिम्मेदारियों में पटरी के सम्पार बिंदुओं पर समरस्याओं को देखना, यात्रा के बाद ट्रेनों को यार्ड में सुरक्षित करना, लोको पायलट और गार्ड को लिखित सूचनाएं पहुंचाना और अन्य काम शामिल हैं। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया यादव की मौत की वजह उनपर काम का ज्यादा बोझ था। इससे न सिर्फ ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सीधे तौर पर खतरे में पड़ रहा है, बल्कि परिचालन से जुड़े हजारों अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की जान भी जोखिम में पड़ रही है। ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसो. के केंद्रीय सांगठनिक सचिव साई प्रसाद ने कहा, एक जुलाई को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गुडमा स्टेशन पर गंभीर मानसिक और शारीरिक थकान के विनाशकारी परिणाम दर्दनाक ढंग से सामने आए।

कंपनियां कार्यबल बढ़ाने के बजाय एआई, विशेष कौशल को दे रही हैं प्राथमिकता

नई दिल्ली/भाषा। कंपनियां अब बड़े पैमाने पर भर्ती करने के बजाय कृत्रिम मेधा (एआई) की समझ रखने वाले, गुणवत्ता और विशेष कौशल वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही है।

अप्रैल की कर्मचारियों की भर्ती के बारे में सूचना देने वाली इकाई अप्रैल रिपोर्ट की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ‘भारत में कार्य : वित्त वर्ष 2026-27 भर्ती रुझान’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार, देश का नियुक्ति बाजार नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां कंपनियां संख्या के बजाय गुणवत्ता आधारित भर्तियों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। यह अध्ययन 12 क्षेत्रों के 11,418 वरिष्ठ मानव संसाधन, प्रतिभा प्रबंधन और कारोबारी अधिकारियों की राय पर आधारित है। अप्रैल रिपोर्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हुसैन टिगवाला ने कहा, भारत का भर्ती परिदृश्य अब संख्या आधारित नहीं



बल्कि सटीकता पर केंद्रित हो रहा है। एआई आधारित अर्थव्यवस्था में टिकाऊ वृद्धि इस बात से परिभाषित नहीं होगी कि किसी कंपनी में कितने लोग कार्यरत हैं, पर इससे होगी कि वे कैसे जरूरत के हिसाब से प्रतिभाओं की पहचान और चयन करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 10 में से आठ कंपनियां अपने निर्धारित भर्ती लक्ष्य हासिल नहीं कर सकीं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान चुनौती योग्य प्रतिभा की उपलब्धता से अधिक भर्ती प्रक्रिया के क्रियान्वयन से जुड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है

कि तीन से आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवर विभिन्न क्षेत्रों में सबसे अधिक मांग वाले कर्मचारी बनकर उभरे हैं। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और वैश्विक क्षमता केंद्रों में हो रहे पुनर्गठन के कारण अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ने की संभावना बनी है। रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिशत कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भर्ती की स्थिति को स्थिर मानती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पदों को भरने में आठ से 12 सप्ताह से लेकर 12 से 20 सप्ताह तक का समय लग रहा है।

स्टीलथ युद्धपोत महेन्द्रगिरि को 11 जुलाई को नौसेना में किया जाएगा शामिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों सहित उन्नत हथियारों तथा अत्याधुनिक संसेर प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टीलथ युद्धपोत महेन्द्रगिरि को 11 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि नौसेना के

युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) द्वारा डिजाइन किए गए और मुंबई की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने निर्मित ‘महेन्द्रगिरि’ परियोजना 17ए के तहत नीलगिरि श्रेणी का छठा युद्धपोत है। उन्होंने बताया कि यह वायु रोधी, सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी अभियानों को अंजाम देने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि यह समुद्री सुरक्षा, शक्ति प्रदर्शन, बेहतर मजबूती, कम खराब पहचान क्षमता और उच्च स्तर की स्वचालन तकनीक से युक्त इस युद्धपोत में

तैनाती जैसे अभियानों के लिए भी उपयुक्त है। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह युद्धपोत स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों एवं संसेरों से लैस है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता, व्यापक पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली तथा एकीकृत युद्ध प्रबंधन प्रणाली शामिल है।’’ उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक स्टीलथ विशेषताओं, बेहतर मजबूती, कम खराब पहचान क्षमता और उच्च स्तर की स्वचालन तकनीक से युक्त इस युद्धपोत में



आधुनिक ‘कम्बाइंड डीजल ऑर गैस’ (सीओडीओजी) प्रणोदन प्रणाली लगी है, जिससे यह समुद्री अभियानों की पूरी श्रृंखला में उच्च

गति और लंबी परिचालन क्षमता प्रदान करता है।

नौसेना ने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक सवदेशी सामग्री

से निर्मित महेन्द्रगिरि सरकार की ‘अल्पनिर्भर भारत’ पहल का उच्चक उदाहरण है। नौसेना के अनुसार, इस युद्धपोत का नाम पूर्वी घाट की महेन्द्रगिरि पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह दृढ़ता, शक्ति और अडिग संकल्प का प्रतीक है। नौसेना ने कहा कि यह युद्धपोत भारत के समुद्री हितों की रक्षा करते हुए एक प्रभावी बल गुणक के रूप में कार्य करेगा और सुरक्षित, स्थिर तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में योगदान देगा। यह युद्धपोत 30 अप्रैल को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(एमडीएल) में नौसेना को सौंपा गया था। इसके निर्माण में भारतीय उद्योगों के व्यापक नेटवर्क ने योगदान दिया है, जिनमें कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। इससे रोजगार सृजन के साथ देश के रक्षा औद्योगिक आधुनिकीकरण को भी मजबूती मिली है।

नौसेना ने कहा कि इस युद्धपोत का सेवा में शामिल होना परियोजना 17ए कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कार्यक्रम के तहत बने जहाजों में परियोजना 17 (शिवालिंक श्रेणी) की तुलना में

उन्नत हथियार और संसेर प्रणाली लगी हुई है। नीलगिरि श्रेणी (परियोजना 17ए) का पांचवां जहाज स्टीलथ युद्धपोत ‘दुनागिरि’, अत्याधुनिक हथियार एवं संसेर प्रणालियों से लैस है। उसे 21 जून को कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। युद्धपोत दो अन्य अग्रिम पंक्ति के प्लेटफॉर्म-सर्वेक्षण पोत (लाज) ‘संशोधन’ और अर्नाला श्रेणी के चौथे पनडुब्बी रोधी वारफेयर शैलो ‘वाटर क्राफ्ट’ ‘अग्रय’ के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया था।



अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/बाघा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सोमवार को पूर्वी कोलकाता में उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। शाह पश्चिम बंगाल की राजधानी के एक दिवसीय दौरे पर हैं और वह जनसंघ के संस्थापक मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिमा निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे।

अमित शाह ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

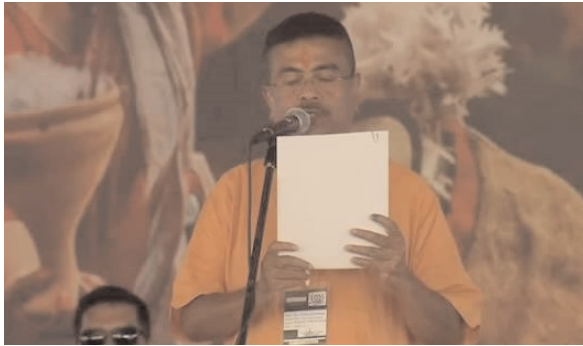
कोलकाता/बाघा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के भवानीपुर इलाके में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आवास पर जाकर जनसंघ के संस्थापक को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। शाह मुखर्जी की जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोलकाता के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, भाजपा की

राज्य इकाई के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, मंत्रियों और भाजपा विधायकों के साथ शहर के न्यू टाउन इलाके में मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जनसंघ संस्थापक के आवास पर पहुंचे। मुखर्जी के आवास पर, शाह ने उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से पहले उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री शाम को विश्व बांग्ला मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें राज्य के भाजपा नेता, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हो सकते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल के हर घर में मिलेगा स मान : मुख्यमंत्री शुभेंदु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/बाघा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोमवार को कहा कि जिस सम्मान के साथ राज्य के सभी स्कूलों में 'वंदे मातरम्' गाया जाता है, डॉ. मुखर्जी को भी बंगाल के हर घर में उसी सम्मान के साथ याद किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने डॉ. मुखर्जी के देश के प्रति योगदान को लोगों के सामने नहीं रखा। उन्होंने



दावा किया कि डॉ. मुखर्जी की मुख्य भूमिका के कारण ही पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना। उन्होंने कहा, "जिस तरह स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाता है, उसी तरह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी राज्य

कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में डॉ. मुखर्जी ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में वाम मोर्चे के 34 वर्ष के शासन और तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 वर्षों के दौरान डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र के प्रति योगदान को लोगों के सामने नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी की भूमिका के कारण ही पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना, अन्यथा यह तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा होता। मुख्यमंत्री ने कहा, उस स्थिति में क्या होता, इसकी कल्पना आज

सोशल मीडिया पर सामने आ रही अनेक पोस्ट और खबरों के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के विचारों के अनुरूप काम करेगी। छह जुलाई, 1901 को जन्मे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून, 1953 को श्रीनगर में हिरासत के दौरान निधन हो गया था। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की मांग करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का अभियान चलाया था। केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।

भाजपा ने 30 दिन जेल में रहने पर मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक का विरोध करने पर कांग्रेस को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बाघा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाने के प्राधान्य वाले विधेयक को इसलिए विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसे भ्रष्टाचार करने से नहीं रोका जाना चाहिए। भाजपा की यह टिप्पणी कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश के इस बयान के एक दिन बाद आई है कि यह संविधान संशोधन विधेयक विरोधियों को राजनीतिक रूप से परेशान करने के मकसद

से लाया गया है और उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही के समान मानक तय करना है। पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा, कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें लगता है कि जेल में रहते हुए भी सरकार चलाया जारी रखा। लगता है कि भ्रष्टाचार करना उनका अधिकार है। वे भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं और अगर कोई उन्हें पकड़ ले, तो वे उल्टी-धड़क रोने लगते हैं। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और अपराध को अपना अधिकार समझने की इस सोच को खत्म किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते



हुए पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाया जारी रख सकता है। उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार का कोई पदाधिकारी जेल जाता है, तो वह इस्तीफा नहीं देगा। हमने अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा देखा, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी सरकार चलाया जारी रखा। क्या प्रशासनिक तौर पर ऐसा मुमकिन है? यह ईमानदारी का भी सवाल है। पूनावाला ने विपक्षी दलों पर सार्वजनिक पद से इस्तीफे के पक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, पहले तो वे (विपक्षी नेता) एक आरोप का संकेत भर मिलने पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे। अब जब

अदालतें उन्हें एक के बाद एक मामलों में जेल भेज रही हैं, तो वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों और आम नागरिकों के लिए एक समान मानक की वकालत की। पूनावाला ने पूछा, अगर कोई आम आदमी जेल जाता है, तो क्या उसे एक दिन भी अपनी नौकरी जारी रखने की इजाजत मिलेगी? उसे तुरंत निर्लंबित कर दिया जाएगा। तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए अलग कानूनी पैमाना क्यों होना चाहिए? विधेयक को पहले ही संसद की संयुक्त सभा के पास भेजा जा चुका है और विपक्षी दलों को सीधे इसका विरोध करने के बजाय समिति की सिफारिशों का इंतजार करना चाहिए।



कांवड़ यात्रा की तैयारियों का डीआईजी ने लिया जायजा

मेरठ/बाघा। आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) कलानिधि नैथानी ने सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी व्यवस्था, पाकिंग, साफ-सफाई और यातायात प्रबंधन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, डीआईजी ने थाना सिविल लाइन, लालकुर्ती, देहली गेट, रेलवे रोड और सदर बाजार क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने घंटाघर स्थित पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय में कांवड़ नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया।

पुलिस के अनुसार नैथानी को निरीक्षण के दौरान कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जबकि कुछ का एंगल 'सही नहीं था। डीआईजी ने सभी कैमरों को तत्काल चालू करने तथा उनके एंगल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नैथानी ने सभी प्रमुख चौराहों और कांवड़ मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों तक नियंत्रण कक्ष से एकीकृत पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। डीआईजी ने केंद्र स्थित बाबा ओघड़नाथ मंदिर का भी निरीक्षण किया और पाकिंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही की समीक्षा की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान नैन्सी चौराहा और दर्शन एकेडमी पाकिंग स्थल पर साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने मंदिर परिसर और आसपास नीचे लटके बिजली के तारों को कसने तथा सीसीटीवी कैमरों की दृश्य सीमा में आड़े आ रही पेड़ों की टहनियों की कटाई कराने की भी निर्देश दिए।



लोस ने सांसदों से कहा : प्रश्नकाल समाप्त होने तक उत्तर सार्वजनिक नहीं कर सकते

नई दिल्ली/बाघा। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को याद दिलाया है कि प्रश्नकाल में मंत्रियों द्वारा पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए जाने तक लिखित उत्तरों की सामग्री को "अत्यंत गोपनीय" माना जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों के उत्तरों की सामग्री भी सदन में प्रश्न पूछे जाने और उसका उत्तर दिए जाने तक "अत्यंत गोपनीय" रहेगी। सचिवालय ने कहा कि यदि किसी प्रश्न पर सदन में मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता है, तो प्रश्नकाल समाप्त होने तक उस प्रश्न का उत्तर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। बीते शनिवार को जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि लिखित प्रश्नों के उत्तरों को तब तक गोपनीय रखा जाएगा, जब तक उन्हें सदन के पटल पर नहीं रखा जाता और प्रश्नकाल समाप्त नहीं हो जाता। बुलेटिन में कहा गया कि किसी प्रश्न का उत्तर उसी रूप में अंतिम माना जाएगा, जिस रूप में वह किसी निर्धारित तिथि के लिए सदन की कार्यवाही में प्रकाशित होता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सांसदों ने अपने प्रश्नों के उत्तर संसद के संबंधित अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक किए जाने से पहले ही मीडिया के साथ साझा कर दिए।

अयोध्या मुद्दे पर आस्था से किया जा रहा है समझौता : अखिलेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/बाघा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 'सत्ता का संघर्ष' होने का आरोप लगाया एवं कहा कि अयोध्या में लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से समझौता किया जा रहा है। यादव ने प्रदेश पार्टी

मुख्यालय पर दल के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रेसवादी में भाजपा पर आरोप लगाया कि इस पार्टी का नेतृत्व लोगों की धार्मिक आस्था की रक्षा करने से ज्यादा अंदरूनी झगड़े को लेकर फिर्कमंद है। उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, फिर



सत्ता का संघर्ष है। उन्हें आस्था या भक्ति की कोई चिंता नहीं है।" यादव ने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोग खजाने के लालच में 'अंधे' हो गए हैं और यह झगड़ा भाजपा के अंदर नियंत्रण की लड़ाई को जाहिर

करता है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कथित चढ़ावा चोरी मामले की विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की जांच खुद भाजपा की अंदरूनी खींचतान को उजागर करती है। उन्होंने कहा, अगर यह प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई या आयकर विभाग का मामला होता, तो जांच दिल्ली के हाथ में होती। अगर इससे पहले कि दिल्ली इस बारे में सोच पाती, लखनऊ ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। यह सत्ता के संघर्ष की वजह से हो रहा है।

मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बाघा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसकी नीतियों के कारण देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश यात्रा करने वाले और विदेशों में रहने वाले लोग आज भारतीय पासपोर्ट की ताकत और सम्मान को जानते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "मोदी सरकार की नीतियां भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में दावा किया था कि विदेश यात्रा करने वाले और विदेशों में रहने वाले



लोग आज भारतीय पासपोर्ट की ताकत और सम्मान को जानते हैं। वह 'ताकत' आखिर दिखाई कहां देती है? तथ्य उनके दावों का समर्थन नहीं करते।" खरगे के मुताबिक, एक वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 2013 में 74वें स्थान से जून, 2026 में 80वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को वर्ष 2026 में 125वां स्थान दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सेवाओं में सुधार करने के बजाय मोदी सरकार ने पासपोर्ट बनवाना और महंगा कर दिया है।

उच्च न्यायालय का राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

लखनऊ/बाघा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच का आदेश देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे निरस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने और मंदिर के वित्तीय मामले का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैम) से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीठ ने याचिका के गुण-दोष की जांच करने से इनकार करते हुए मामले को निरस्तारित कर दिया।

भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहला मौका मिलते ही बांकीपुर छोड़ दिया : प्रशांत किशोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/बाघा। जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर संसद पहुंचने का पहला अवसर मिलते ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को "छोड़ देने" का आरोप लगाया। पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन लगातार पांचवीं बार इस सीट से विजयी रहे थे। इस उपचुनाव में इस सीट से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे किशोर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा



का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात विधानसभा की अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। किशोर ने कहा, मुझे पता है कि भाजपा बांकीपुर को अपना गढ़ मानती है। यहां के मतदाताओं ने बार-बार नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। लेकिन नितिन नवीन ने उन्हें भूलने में

निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान का प्रबंधन कर चुके आईपैक (आई-पीएसी) के संस्थापक किशोर ने कहा, हमारे सामने अमित शाह का उदाहरण है। जब वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब गुजरात विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने अपनी विधानसभा सीट नहीं छोड़ी थी। नितिन नवीन के लिए दिल्ली जाना कोई मजबूरी नहीं थी। वह उनका अपना फैसला था। अमित शाह 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और 2017 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने तक गुजरात की नारनपुरा विधानसभा सीट से विधायक बने रहे।



आगरा में तेजो महालय मामले में केंद्र, एसआई से जवाब तलब

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रयागराज/बाघा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में भगवान श्री अग्नेश्वर महादेव नामनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर और ताजमहल के मामले में दायर रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। यह याचिका आगरा जनपद न्यायालय के उन आदेशों को खिलाफ दायर की गई है जिसमें दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिप्टीजज) और अपर जिला न्यायाधीश ने विवादित परिसरों का सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिकांश आयोग गठित करने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने

गठित की अधिवक्ता आयोग दलित करने और विवादित परिसरों की फोटोग्राफी के लिए उनका आवेदन गलत ढंग से खारिज किया गया, तथा इसके बाद पुनरीक्षण याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, यद्यपि विवाद पर निर्णय के लिए यह आवश्यक है। अधिवक्ता जैन की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने केंद्र और एएसआई को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और इस रिट याचिका में चौथे प्रतिवादी पंकज कुमार वर्मा को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सौम्या गौरीवास्तव के मुताबिक, वर्ष 2015 में एक घोषणात्मक वाद दायर किया गया था जिसमें यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया था कि ताजमहल परिसर में भगवान श्री अग्नेश्वर महादेव नामनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर है।

धार्मिक स्वतंत्रता दूसरों की भावनाओं को आहत करने की अनुमति नहीं देती : कलकत्ता उच्च न्यायालय

कोलकाता/बाघा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से एक व्यक्ति की सहायक प्राथमिक पक्ष पर नियुक्ति को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन इसे दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह फैसला पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन कॉलेज की उस याचिका पर दिया, जिसमें चार सितंबर, 2025 को तमाल दासगुप्ता को संस्थान में अंग्रेजी का सहायक प्राध्यापक नियुक्त करने के एकल पक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति देवांगु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शखर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि उम्मीदवार के सोशल मीडिया पोस्ट दूसरे धर्मों के मानने वालों की भावनाएं आहत करने वाली थीं। पीठ ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि दासगुप्ता ने अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के बारे में कई विचार व्यक्त किए थे। अदालत ने उम्मीदवार की दलील को अस्वीकार कर दिया कि कॉलेज द्वारा उन्हें नौकरी न देने के फैसले ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है। अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग की ओर से इस पद पर दासगुप्ता को नियुक्त करने की सिफारिश किए जाने से पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। इन पोस्ट में उन्होंने धर्मों, रामकृष्ण मिशन (जिसका यह महाविद्यालय एक हिस्सा है) के कामकाज और मिशन के संतों के बारे में कई विचार व्यक्त किए थे।



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

स्क्रीन टाइम से ज्यादा संस्कार जरूरी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं, वे अत्यंत प्रासंगिक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक स्क्रीन टाइम का गलत असर हो रहा है। वहीं, पारिवारिक माहौल भी ऐसा होना जा रहा है, जहां बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या टीवी पर क्या देख रहे हैं – यह मालूम करने के लिए माता-पिता के पास समय नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चों को सबसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा देना काफी है। पहले, पारिवारिक मार्गदर्शन के कारण बच्चे अनुशासित रहते थे। अब इसका अभाव होता जा रहा है। भागवत ने सत्य कहा कि नई पीढ़ी को बातचीत करने की जरूरत है। उसके अकेलेपन को दूर करना होगा, जो भीतर घर कर रहा है। आज किशोरों और युवाओं को अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया तक के मशहूर बैंड के नाम मालूम हैं। वे इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब उन्हें महाभारत के योद्धाओं, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में पूछा जाता है तो वे उलझन में पड़ जाते हैं। वे पुस्तकों से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि हर सवाल का जवाब सर्व इंजन या एआई टूल के पास है। वे उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आंखें मूंदकर विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की भरमार है, जिसमें दावा किया जाता है कि ‘बड़े-बुजुर्गों की बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर उन्हें ही सबकुछ पता होता तो आज इतनी समस्याएं नहीं होतीं।’ वास्तव में, यहां मुद्दा समस्याओं का होना या न होना नहीं, बल्कि अनुभव का होना है।

सोशल मीडिया पर कई युवा स्वीकार करते हैं कि वे किशोरावस्था में कुसंगति के कारण शराब, जुआ और चरित्र संबंधी अन्य खराबियों में रुचि लेने लगे थे। उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वे दोस्तों की बातों को ब्रह्मांड का अंतिम सत्य समझते थे। बाद में, उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने अपना अनमोल समय, स्वास्थ्य और धन गंवा दिया। अगर उनके परिवार में इस मुद्दे पर बात की जाती, कोई बुजुर्ग सदस्य उन्हें समझाता तो वे उल बुराइयों से बच सकते थे। कई बच्चों में पढ़ने, आगे बढ़ने और कुछ करने की इच्छाशक्ति नजर नहीं आती। उन्हें माता-पिता द्वारा सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन वे पूरी तरह सुरत दिखाई देते हैं। वे सुबह स्कूल जाने से पहले बहुत धीरे-धीरे तैयार होते हैं। उन्हें यह तो याद रहता है कि आज शाम को एक सेलिब्रिटी के कार्यक्रम का प्रसारण होगा, लेकिन वे शिक्षक द्वारा दिया गया गृहकार्य करना बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। उन्हें अचानक याद आता है कि कल एक विषय का टेस्ट है। उन्हें अपने दोस्तों के जन्मदिन कंठस्थ रहते हैं। किस साल पार्टी में कौनसी ड्रेस पहनी थी, कहां से केक मंगाया था, कौनसा गाना चलाया था, कौन-कौन आया था – ये सब उनकी याददाश्त में हमेशा कैद रहते हैं। दादी-नानी की कहानियां लुप्त होती जा रही हैं। उनकी जगह मोबाइल फोन पर दिखाई देने वाले विदेशी किरदारों ने ले ली हैं। पुरानी कहानियों से स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही था, अच्छी सीख भी मिलती थी। विदेशी किरसे-कहानियां परोस रहे किरदारों में इनका घोर अभाव है। अक्सर वे बच्चों को ऐसे तौर-तरीके अपनाने के लिए कहते हैं, जो भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। ये बच्चे भविष्य में कैसे नागरिक बनेंगे? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बच्चे अच्छी बातें सीखें, अच्छी संगति में रहें, मानसिक रूप से मजबूत बनें, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए सही मार्गदर्शन देना बड़ों की जिम्मेदारी है।

ट्वीटर टॉक

अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर वैश्य मित्र रत्न सम्मान समारोह में उपस्थित सम्मानित लोगों को संबोधित किया। वैश्य समुदाय ने हमेशा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की समझ सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

-अर्जुनराम मेघवाल

, हरित क्रांति के अग्रदूत और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉ. बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि के मौके पर, विधान सौंध के पश्चिमी गेट के पास उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाते और श्रद्धांजलि देते हुए।

-डीके शिवकुमार

राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वीर योद्धा, महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर आज मंगलेश्वर महादेव मंदिर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

-दिया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

संन्यासी का प्रेरक आचरण

एक शिष्य ने परमहंसजी से पूछा कि आम लोग तो सभी सुख-सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन संत-संन्यासियों के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं? परमहंसजी ने जवाब दिया कि आम लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम करने के लिए आजाद हैं, लेकिन संन्यासी कितना भी तपस्वी क्यों न हो, उसे रीतियों से दूर रहना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सुख-सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संत को क्रोध से बचना चाहिए। शिष्य ने पूछा कि संन्यासियों के लिए ही इतने कठिन नियम क्यों बनाए गए हैं? जबकि संन्यासी भी इसी समाज का हिस्सा है, यह भी इंसान ही है। परमहंसजी ने कहा कि त्याग की शिक्षा एक संन्यासी नहीं देगा तो और कौन देगा, संन्यासी अपने ज्ञान और कर्म से समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने की सीख देता है। संन्यासी अपने आवरण से समाज को बताता है कि इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए किसी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए, त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, ("Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वगीकृत, टैंडर एवं सजायटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उद्योगों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरवाह नहीं बना सकता। — **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

सामयिक

साइबर संजाल: डिजिटल दुनिया का काला सच

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित हो रही बाल यौन शोषण सामग्री और आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर सख्त रुख अपनाने हुए कई डिजिटल कंपनियों से जवाब-तलब किया। कुछ समय पहले ‘इंस्टाग्राम’ पर ऐसे विज्ञापनों के सामने आने से व्यापक विवाद खड़ा हुआ, जिनके माध्यम से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए और यह स्पष्ट किया कि डिजिटल मंचों को केवल तकनीकी सेवा प्रदाता मानकर उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह घटना केवल एक कंपनी या एक मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गंभीर संकट का संकेत है, जिसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक हिस्सा अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। जिस तकनीक का उद्देश्य ज्ञान, संवाद और विकास था, वही तकनीक आज अनेक रूपों में अपराध, धोखाधड़ी, मानसिक शोषण और सामाजिक विघटन का माध्यम भी बन रही है। ऐसे समय में साइबर संजाल के उजले और काले दोनों पक्षों को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

इकीसवीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है। इंटरनेट ने दुनिया को सघन एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। आज शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, सरकारी सेवाएं और सामाजिक संवाद लगभग पूरी तरह डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो चुके हैं। एक क्लिक पर जानकारी उपलब्ध हो जाती है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग कुछ ही सेकंड में एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं और छोटे-से गांव का व्यक्ति भी वैश्विक बाजार तक पहुंच बना सकता है। डिजिटल क्रांति ने विकास की गति को अभूतपूर्व बनाया है। भारत में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना ने करोड़ों लोगों का जीवन सरल बनाया है। लेकिन हर तकनीकी की तरह इंटरनेट का भी दूसरा चेहरा है, जो उतना ही भयावह और घातकजनक है।

साइबर संजाल का सबसे बड़ा खतरा यह है कि अपराध अब केवल सड़कों या बंद कमरों तक सीमित नहीं रहे। अपराधियों ने डिजिटल दुनिया को अपना नया अड्डा बना लिया है। साइबर ठगी, पहचान की चोरी, बैंक खातों से धन की निकाली, फर्जी निवेश योजनाएं, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, अश्लील सामग्री का प्रसार, महिलों और बच्चों का डिजिटल उत्पीड़न, फर्जी समाचार, धार्मिक और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले संदेश, साइबर बुलिंग तथा हैकिंग जैसी

घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इंटरनेट ने अपराधियों को ऐसा मंच उपलब्ध कराया है, जहां वे अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर हजारों लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि साइबर अपराधों का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। सबसे ज्यादा घात का विषय बच्चों और किशोरों की सुरक्षा है। आज की नई पीढ़ी बचपन से ही मोबाइल और इंटरनेट के संपर्क में आ जाती है। पढ़ाई, मनोरंजन और खेल के नाम पर वे घंटों ऑनलाइन रहते हैं। अपराधी इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। फर्जी प्रोफाइल बनाकर बच्चों से दोस्ती करना, उनकी निजी जानकारी प्राप्त करना, अश्लील सामग्री भेजना, मानसिक रूप से प्रभावित करना और अंततः उनका शोषण करना आज एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। कई बार बच्चे अनजाने में ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना उनके लिए कठिन हो जाता है। माता-पिता

सवाल यह उठता है कि क्या इन मंचों की केवल तकनीकी भूमिका है या फिर उन पर प्रकाशित सामग्री के प्रति उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है? यदि किसी मंच का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है, तो उसकी जवाबदेही तय होना स्वाभाविक है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं हो सकता कि सामग्री उपयोगकर्ताओं ने डाली है।

और शिक्षकों की थोड़ी-सी लापरवाही बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पूरे विमर्श के केंद्र में हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और अन्य मंच करोड़ों लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। इन माध्यमों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नया विस्तार दिया है, लेकिन यही मंच नरकर फैलाने, अफवाहें फैलाने, अश्लील सामग्री प्रसारित करने और अपराधियों को नए शिकार खोजने का माध्यम भी बनते जा रहे हैं।

सवाल यह उठता है कि क्या इन मंचों की केवल तकनीकी भूमिका है या फिर उन पर प्रकाशित सामग्री के प्रति उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है? यदि किसी मंच का एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है, तो उसकी जवाबदेही तय होना स्वाभाविक है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं हो सकता कि सामग्री उपयोगकर्ताओं ने डाली है। वास्तव में डिजिटल कंपनियों के एल्गोरिदम का उद्देश्य, उपयोगकर्ता को अधिक समय तक मंच पर बनाए रखना होता है। इसके लिए वे उपयोगकर्ता की रुचियों

के अनुरूप सामग्री दिखाते हैं। कई बार यही एल्गोरिदम सनसनीखेज, हिंसक या अश्लील सामग्री को भी अधिक प्रसारित कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सामग्री पर लोगों की प्रतिक्रिया अधिक होती है। इससे अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। इसलिए केवल सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन तकनीकी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा आवश्यक है, जो ऐसी सामग्री को लोकप्रिय बनाती हैं। साइबर अपराध केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन चुके हैं। आज सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले, महत्वपूर्ण संस्थानों के डाटा की चोरी, रक्षा प्रतिष्ठानों पर हैकिंग के प्रयास और संवेदनशील सूचनाओं की जासूसी जैसी घटनाएं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। किसी देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, रेलवे नेटवर्क या स्वास्थ्य सेवाओं पर साइबर हमला पूरे राष्ट्र को संकट में डाल सकता है। इसलिए

पर निजी सूचनाओं को सीमित रखना जैसी छोटी-छोटी सावधानियां बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। इसके साथ ही बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की शिक्षा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परिवारों में डिजिटल अनुशासन विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना।

शिक्षा व्यवस्था में भी साइबर नैतिकता को शामिल किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल कंप्यूटर चलाना नहीं, बल्कि इंटरनेट का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना भी सिखाया जाना चाहिए। उन्हें यह समझाना होगा कि ऑनलाइन दुनिया में भी वही नैतिक मूल्य लागू होते हैं, जो वास्तविक जीवन में होते हैं। किसी की निजता का सम्मान करना, फर्जी समाचार साझा न करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करना और डिजिटल माध्यम का सकारात्मक उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी ओर, तकनीकी कंपनियों को भी केवल मुनाफे की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, संचिध सामग्री की त्वरित पहचान, बाल यौन शोषण सामग्री के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता, फर्जी खातों पर कठोर कार्रवाई तथा सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्रभावी सहयोग जैसे कदम अनिवार्य बनने चाहिए। डिजिटल मंचों को यह स्वीकार करना होगा कि उनके करोड़ों उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेट स्वयं अपराधी नहीं है। दोष तकनीकी का नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग का है। जिस इंटरनेट ने शिक्षा को घर-घर पहुंचाया, छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजार दिया, मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ा, किसानों तक नई जानकारी पहुंचाई और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत किया, वही इंटरनेट यदि अपराधियों के हाथ में पड़ जाए तो विनाशकारी भी बन सकता है। इसलिए समाधान तकनीक से दूरी बनाना नहीं, बल्कि तकनीक का विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग करना है। वास्तव में साइबर संजाल आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य वास्तविकता है। इससे मुंह मोड़ना संभव नहीं और न ही उचित है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। सरकार सशक्त कानून बनाए, डिजिटल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षण संस्थान साइबर जागरूकता बढ़ाएं और प्रत्येक नागरिक डिजिटल अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाए। तभी इंटरनेट मानवता के विकास का सशक्त माध्यम बना रहेगा, न कि अपराध और शोषण का अंधकारमय जाल। तकनीक तभी सार्थक है, जब वह मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर बनाने का माध्यम बने।

नजरिया

गगनयान के परीक्षणों में इसरो को मिली बड़ी सफलता

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता और दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपने इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट और सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (डजडएफ) यानी सॉल्वे सॉलिड मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अत्यंत जटिल तकनीक में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग चार सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना और तीन दिन के सफल मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस पूरे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू अंतरिक्ष यात्रियों की पुख्ता सुरक्षा है और हाल ही में किए गए ये परीक्षण सीधे तौर पर इसी सुरक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

सॉल्वे सॉलिड मोटर का सफल परीक्षण क्रू एस्कैप लिस्टम की विध्वंसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। यह एक विशेष प्रकार का रॉकेट है जिसे इसरो ने विशेष रूप से केवल गगनयान के क्रू मॉड्यूल के उड़ान परीक्षणों के लिए विकसित किया है। इस सॉलिड मोटर को पीएसएलवी रॉकेट के स्टैप ऑन मोटर के आधार पर तैयार किया गया है लेकिन इसमें गगनयान मिशन की विशेष और सख्त आवश्यकताओं के अनुसार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें धीमी गति से जलने वाले प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया है ताकि यह आवश्यक समय तक लगातार और नियंत्रित ऊर्जा प्रदान कर सके। इसके साथ ही इसमें सेकेंडरी इंजनशन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी अत्याधिक उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक रॉकेट की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है। इस मोटर का मुख्य काम उड़ान के दौरान किसी भी अपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को मुख्य रॉकेट से तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर खींच ले जाना है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया यह ग्राउंड टेस्ट यह साबित करता है कि मोटर का प्रदर्शन इसरो के



कड़े मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है।

इसके साथ ही इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट भी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से अपना मिशन पूरा करके वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसकी गति अत्यधिक तीव्र होगी। इस भयंकर गति को कम करने और भारी क्रू मॉड्यूल को समुद्र की सतह पर बहुत ही सुरक्षित रूप से उतारने के लिए पैराशूट प्रणाली का बिना किसी चूक के काम करना आवश्यक है। इसरो ने इस रिकवरी प्रणाली में कुल दस पैराशूट्स का एक जटिल और अबूक नेटवर्क तैयार किया है। इस प्रणाली के तहत सबसे पहले एपेक्स कवर अलग होता है जिसके तुरंत बाद गति को कम करने के लिए दो ड्रॉग पैराशूट खुलते हैं। जब मॉड्यूल की तेज गति कुछ हद तक नियंत्रित हो जाती है तो अंत में तीन विशाल मुख्य पैराशूट खुलते हैं जो क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के पानी में बेहद सुरक्षित और धीमी गति से लैंड कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्पेल्लिडाउन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट की शानदार सफलता यह सुनिश्चित करती है कि पैराशूट खुलने की टाइमिंग और उनका तनाव सहने की क्षमता बिल्कुल सटीक है।

गगनयान मिशन भारत के लिए कई मायनों में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। इंसानों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजना केवल उपग्रह भेजने से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए इसरो अपने सबसे भारी और भरोसेमंद रॉकेट एलवीएम थ्री का उपयोग कर रहा है जिसे मानव उड़ान के अनुकूल बनाने के लिए ह्यूमन रेटेड किया जा रहा है। ह्यूमन रेटिंग का सीधा अर्थ यह है कि रॉकेट का हर एक पुर्जा और हर एक प्रणाली शत प्रतिशत सुरक्षित और भरोसेमंद होनी

चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मॉड्यूल के भीतर एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए इसरो एक विशेष पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार ऑक्सीजन प्रदान करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी को नियंत्रित रखेगी। यह उन्नत प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो भारतीय वैज्ञानिकों की असीमित बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। अंतरिक्ष से वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। जब यह मॉड्यूल वायुमंडल की घनी परतों से तेज गति से टकराता है तो घर्षण के कारण उसका बाहरी तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक और जानलेवा गर्मी से अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए क्रू मॉड्यूल के बाहरी हिस्से पर एक विशेष प्रकार का थर्मल हीट शील्ड लगाया गया है। यह शील्ड मॉड्यूल के भीतर के तापमान को बिल्कुल सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसरो ने इस हीट शील्ड का निर्माण भी स्वदेशी रूप से किया है और इसके कई सफल परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। वापसी के अंतिम चरण में भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही क्रू मॉड्यूल समुद्र में गिरगा नौसेना के कुशल गोताखोर और विशेष जहाज तुरंत वहां पहुंचकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसके लिए इसरो और भारतीय नौसेना मिलकर लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं ताकि रिकवरी प्रक्रिया में एक सेकंड की भी कोई चूक न हो।

इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के चार बेहद अनुभवी टेस्ट पायलटों को चुना गया है जिन्होंने रूस में अपना शुरुआती कड़ा प्रशिक्षण

सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब वे भारत में गगनयान मिशन के लिए विशेष रूप से स्थापित अत्याधुनिक सुविधाओं में आगे का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान के हर छोटे बड़े चरण और किसी भी अपात स्थिति से निपटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। गगनयान मिशन की सफलता से भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने पूरी तरह से अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। इससे पहले केवल रूस अमेरिका और चीन ने ही यह आसाधारण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता भारत की वैश्विक छवि को एक नई उंचाई पर ले जाएगी और अंतरिक्ष कूटनीति के क्षेत्र में भारत का दबदबा और भी अधिक मजबूत होगा।

इसके अलावा गगनयान मिशन का भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह महावाकंक्षी मिशन देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। इससे युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बहुत अधिक बढ़ेगी और देश को नए वैज्ञानिक तथा कुशल इंजीनियर मिलेंगे। इस मिशन के लिए कई नई और उन्नत तकनीक का विकास किया जा रहा है जिनका भविष्य में चिकित्सा उद्योग और अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक उपयोग किया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही शानदार संकेत है। यह मिशन भारत के लिए केवल एक वैज्ञानिक परियोजना मात्र नहीं है बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के सपनों असीम आकांक्षाओं और राष्ट्रीय गौरव का सर्वोच्च प्रतीक है।

अंत में यह कहना बिल्कुल सही और तर्कसंगत होगा कि सॉल्वे सॉलिड मोटर और इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट की इस हालिया सफलता ने गगनयान मिशन की नींव को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस जटिल और महंगी तकनीक को अपने ही देश में विकसित करके एक मिशाल कायम की है। अब यह स्वर्णिम दिन दूर नहीं है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट में बैकवर अंतरिक्ष की अलंत यात्रा करेगा और वहां तिरंगे का मान बढ़ाएगा। यह महान सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत है और पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों की इस शानदार उपलब्धि पर बहुत गर्व है। गगनयान मिशन के हर चरण की सफलता के साथ भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की दिशा में पूरे आत्मविश्वास के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

